FUNDAMENTAL RIGHTS AND AMENDMENTS

HTTPS://CHITRABAZAR.COM/

मौलिक अधिकार :-

अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है कि भारतीय संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए "राज्य" का गठन क्या होता है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून

अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वह संविधान के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाया गया हो, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अनादर करता है, अमान्य होगा। यह न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार.

सूत्र: अनुच्छेद 14 = समानता का अधिकार

उदाहरण: कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

सूत्र: अनुच्छेद 15 = भेदभाव का निषेध (धर्म+जाति+जाति+लिंग+जन्मस्थान)

उदाहरण: शैक्षणिक संस्थान इन कारकों के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

सूत्र: अनुच्छेद 16 = (सार्वजनिक रोजगार) में अवसर की समानता

उदाहरण: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी के अवसरों में कोई भेदभाव नहीं।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत.

सूत्र: अनुच्छेद 17 = अस्पृश्यता का अंत

उदाहरण: किसी भी रूप में अस्पृश्यता के आचरण पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन.

सूत्र: अनुच्छेद 18 = उपाधियों का उन्मूलन

उदाहरण: भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधियाँ स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

अनुच्छेद 19: बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण।

सूत्र: अनुच्छेद 19 = (भाषण की स्वतंत्रता + आदि) का संरक्षण

उदाहरण: नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ और आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

सूत्र: अनुच्छेद 20 = (अपराधों के लिए दोषसिद्धि) के संबंध में संरक्षण

उदाहरण: आत्म-दोषारोपण और दोहरे ख़तरे से सुरक्षा।

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।

सूत्र: अनुच्छेद 21 = (जीवन + व्यक्तिगत स्वतंत्रता) की सुरक्षा

उदाहरण: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण।

सूत्र: अनुच्छेद 22 = संरक्षण (कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत)

उदाहरण: गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण

अनुच्छेद 22 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी पाने का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार शामिल है। यह उचित प्राधिकार के बिना निवारक हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। यह घोषणा करता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम कानून द्वारा दंडनीय अपराध हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य शोषण को रोकना और व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करना है।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।

अनुच्छेद 24 कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है।

अनुच्छेद 25: धर्म की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव भी शामिल है। यह धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति

अनुच्छेद 27 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखता है।

अनुच्छेद 28: शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति

अनुच्छेद 28(1) में प्रावधान है कि पूर्ण रूप से राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28(3) धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है यदि यह स्वैच्छिक है और निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है।

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 29 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकें।

अनुच्छेद 30: शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है। यह उनकी सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वायत्तता की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 31: संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

अनुच्छेद 31, जिसे 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसने राज्य द्वारा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की। हालाँकि, यह अनुच्छेद अब लागू नहीं है।

अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे भारतीय संविधान का "हृदय और आत्मा" माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति देता है।

FOR MOST POPULAR PDF BOOK GO TO WEBSITE

https://chitrabazar.com/english-dictionary/